जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 30 संख्याः 26 प्रभात अजमेर, मंगलवार 26 अगस्त, 2025 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भारत ने ट्रंप से डील करने के लिए ''मर्करी पब्लिक अफेयर्स'' की सेवाएं लीं

यह पोलिटिकल लॉबिइंग फर्म है जिसकी वाइट हाउस में गहरी पैठ है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर लड़ाई अब केवल व्यापारिक मंचों और शिखर सम्मेलनों तक सीमित नहीं रही - यह वॉशिंगटन के प्रभाव वाले क्षेत्रों तक पहुँच चुकी है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत तक की भारी ड्यूटी लगाए जाने की संभावना के बीच, नई दिल्ली ने अपने सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हथियार ''लॉबिइंग'' को सक्रिय कर दिया है। वाइट हाउस से गहरे संबंध रखने वाली एक दूसरे नम्बर की हाई-पावर्ड फर्म को हायर करके भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों या वॉशिंगटन में अपनी रणनीतिक पकड़ को बिना लड़े कमज़ोर नहीं होने देगा।

- ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में अब भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार को काम में लिया है और वह है ''पोलिटिकल लॉबिइंग'' इसके लिए मर्करी पब्लिक अफेयर्स से 1.96 करोड़ रु. में तीन माह का करार किया है।
- वाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रभावशाली चीफ ऑफ स्टाफ सूज़ी वाइल्स से मर्करी की निकटता जग जाहिर है। सूज़ी मर्करी के लिए काम कर चुकी हैं।
- भारत के अलावा डेनमार्क, इक्वाडोर, आर्मेनिया व दक्षिण कोरिया ने भी इस फर्म की सेवाएं ली हैं।
- अमेरिका में लॉबिइंग बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक रुप से विपन्न पाकिस्तान भी 6 ऐसी फर्मों पर प्रति माह 5.2 करोड़ रु. खर्च करता है।

यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (एफएआरए) के तहत हुए अनिवार्य खुलासों के अनुसार, वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ''मरकरी पब्लिक अफेयर्स'' नामक फर्म के साथ तीन महीने का अनुबंध किया है, जिसकी कुल लागत 225,000 (लगभग 1.96 करोड़) है। यह अनुबंध 15 अगस्त से प्रभावी है और इसके तहत मरकरी को संघीय लॉबिइंग, मीडिया आउटरीच, सोशल मीडिया रणनीति, विज्ञापन, और भारत की सार्वजनिक छवि का डिजिटल ऑडिट करना है, जो नवंबर के मध्य तक चलेगा।

इस व्यवस्था को खास बनाने वाली बात यह है कि मरकरी का वर्तमान वाइट हाउस से बेहद नजदीकी संबंध है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की प्रभावशाली चीफ ऑफ स्टाफ सूज़ी वाइल्स पहले मरकरी के वॉशिंगटन और फ्लोरिडा कार्यालयों की प्रमुख रह चुकी हैं और ट्रम्प के 2024 के चुनाव अभियान की अगुआई भी कर चुकी हैं। यह व्यक्तिगत और संस्थागत संबंध भारत को वॉशिंगटन के व्यक्तित्व-प्रधान सत्ता गलियारों में अधिक प्रभावशाली बना सकता है।

भारत इस राह पर अकेला नहीं है। ट्रम्प की सत्ता में वापसी के बाद डेनमार्क, इक्वाडोर, आर्मेनिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने भी मरकरी को हायर किया है। हालांकि नई दिल्ली के लिए स्थिति ज्यादा गंभीर है, क्योंकि नया टैरिफ ढांचा अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, एक ऐसे समय में जब द्विपक्षीय व्यापार भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की रीढ़ बन चुका है।

मरकरी के साथ हुआ यह समझौता वॉशिंगटन में भारत की पहले से मजबूत लॉबिइंग उपस्थिति में एक और कड़ी जोड़ता है। सन् 2023 से भारत ने सालाना 1.8 मिलियन (लगभग 15.7 करोड़) की फीस पर दायर कर रखा है, जिसका नेतृत्व ट्रम्प के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर कर रहे हैं। यह अनुबंध रणनीतिक सलाह, सरकारी संपर्क और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, विशेषकर ऐसे समय में जब वॉशिंगटन भारत की विदेश नीति,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायत चुनाव जल्दी कराने के कोर्ट के आदेश पर रोक लगी

जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से गत 18 अगस्त को प्रदेश की पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाने के आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए। अदालत ने कहा कि समान बिंदु पर खंडपीठ के समक्ष मामला लंबित है।

अपील में अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने बताया कि एकलपीठ ने गत 18 अगस्त को पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने के

- हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर डबल बैंच ने रोक लगाई।

आदेश देते हुए याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी। अपील में कहा गया कि पूर्व में पंचायतों के तीन चरणों में चुनाव हुए थे। ऐसे में संबंधित सरपंचों का कार्यकाल भी अलग-अलग चरणों में पूरा हो रहा है। राज्य सरकार सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इसलिए कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी। वहीं बाद में कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर उन्हें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'धनखड़ के बारे में सच-झूठ की व्याख्या विपक्ष की राय पर आधारित नहीं होनी चाहिए'

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के ''हाउस अरैस्ट'' की चर्चा पर यह बात कही

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 अगस्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने और उसके बाद सार्वजनिक रूप से पूरी तरह गायब रहने को लेकर आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की तो भ्रम और गहरा गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाह की टिप्पणी ने पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे और उनकी गैर मौजूदगी से संबंधित रहस्य को और उलझा दिया है।

- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, धनखड़ के त्यागपत्र में साफ लिखा था वे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें ज्यादा सोच विचार की जरुरत नहीं है।
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केन्द्रीय गृह मंत्री शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाह के स्पष्टीकरण से धनखड़ की गैर मौजूदगी पर रहस्य और गहरा हो गया है।
- जयराम रमेश ने कहा कि शाह यह नहीं बता पाए कि किसानों के हितैषी और इतने मुखर नेता धनखड़ से इस्तीफा देने के बाद कोई संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि धनखड़ ने मानसून सत्र के पहले ही दिन स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा दे दिया था, तब से वे सार्वजनिक जीवन से गायब हैं।

जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ''श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई, 2025 की रात को अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यह अभूतपूर्व था एक दिन बाद, प्रधानमंत्री ने बस उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना दी। आज गृह मंत्री ने कुछ और कहने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही किया है।'' उनकी यह टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और विपक्ष को इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में शाह ने कहा, धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र अपने आप में स्पष्ट है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और सरकार के सदस्यों के प्रति अपने अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए इस आरोप कि धनखड़ को नज़रबंद कर दिया गया है, निराधार हैं।

उन्होंने कहा, ''सच और झूठ की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डूंगरपुर में भारी बारिश, बेणेश्वर धाम टापू बना

माही बांध के गेट खोले जाने के बाद से बेणेश्वर धाम के चारों तरफ पानी भर गया है

डूंगरपुर, 25 अगस्त (निसं)। जिले भर में पिछले दो दिन लगातार तेज व मध्यम गति की बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले के कई तालाब व बांध अपनी भराव क्षमता को पार कर चुके हैं। वहीं जिले का प्रमुख आस्था का केंद्र बेणेश्वर धाम तीन दिन से टापू बना हुआ है। जबसे माही बांध के गेट खोले गए तबसे जिले का सबसे बड़ा धर्मस्थल बेणेश्वर धाम के चारों और पानी ही पानी है। तीन दिन पूर्व वहां पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। सोमवार को यही हालत रही, मौके पर प्रशाशनिक अधिकारी नियुक्त है, ताकि कोई जनहानि न हो। प्रशासन ने बेणेश्वर धाम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

- प्रशासन ने वहां फंसे श्रद्धालुओं को निकाला और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया ताकि हालात पर नज़र रखी जा सके।
- डूंगरपुर जिले के सभी बांध और तालाब लबालब हो गए हैं तथा कई बांध ओवर फ्लो हो रहे हैं।
- कागदर नदी उफान पर है, जिससे देव सोमनाथ पुल पर एक से दो फीट पानी बह रहा है।
- डूंगरपुर शहर में भी बारिश से हालात खराब हैं। सड़कों पर दो से तीन फीट पानी है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि में छुट्टी कर दी गई है।

वहीं जिले के सबसे बड़े बांध सोम कमला आम्बा के सात गेट 1-1 मीटर खोले गये हैं तथा आसपास के काश्तकारों को सावधान कर दिया गया है। इधर लगातार बारिश के चलते पुराने शहर में सड़कें दरिया बन गई है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। डूंगरपुर में भारी बारिश के अलर्ट के चलते सोमवार को स्कूल, मां बाडी केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां रही।

डूंगरपुर शहर के पुराना विजय स्कूल की चार दीवारी का कुछ हिस्सा ढह गया है। हालांकि स्कूल में छुट्टी की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। जिले के कनबा इलाके में सबसे अधिक साढे तीन इंच बरसात हुई है, जबकि डूंगरपुर और देवल में ढाई-ढाई इंच बरसात हुई है। अमरपुरा सहित 7 छोटे-बड़े बांध व तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। कागदर नदी से लगातार पानी की आवक के कारण जहां देवसोमनाथ पुल पर एक से दो फीट पानी बह रहा है, इसलिए दोनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जंतर-मंतर पर फिर डटे किसान

नई दिल्ली, 25 अगस्त। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर प्रदर्शन करने की राह पर हैं। सोमवार को जंतर-मंतर पर हजारों किसानों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग की। किसानों का कहना है कि एमएसपी किसानों के लिए मूल अधिकार के समान है जिसके बिना खेती को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें कर्ज से मुक्ति दे और एमएसपी को कानूनी अधिकार घोषित

- किसानों ने सरकार से एमएसपी देने की मांग की है।

करे जिससे उन्हें अपनी ही फसलों के लिए सही दाम पाने के लिए बार-बार आंदोलन न करना पड़े।

किसानों की महापंचायत में पंजाब से आए सुखविंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले 10-11 वर्षों के कार्यकाल में देश के बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर चुकी है। लेकिन पूरे देश के किसानों का पूरा कर्ज 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों को एकमुश्त कर्ज से मुक्ति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सुदर्शन रेड्डी पर शाह की टिप्पणी पूर्वाग्रह से भरी गलत व्याख्या है'

सुप्रीम कोर्ट के 7 पूर्व न्यायाधीशों सहित 18 पूर्व जजों ने अमित शाह के खिलाफ हस्ताक्षरित बयान जारी किया

नई दिल्ली, 25 अगस्त। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे बचना ही समझदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकुर और जे. चेलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने यह भी कहा कि एक उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से शीर्ष अदालत के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- शाह के खिलाफ बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस चेलमेश्वर, मदन बी.लोकुर, कुरियन जोसेफ, अभय ओका, गोपाल गौडा व विक्रमजीत सेन शामिल हैं।
- सेवानिवृत न्यायाधीशों के समूह ने कहा कि एक उच्च राजनैतिक पदाधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या करने से न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- ज्ञातव्य है कि अमित शाह ने कहा था कि सुदर्शन रेड्डी ने सल्वा जुडुम खत्म करने का फैसला न दिया होता तो नक्सलवाद 2020 में ही खत्म हो जाता।

दरअसल, शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सलवा जुडूम फैसले के बिना वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता।

18 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षिरत बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह फैसला कहीं भी, न तो स्पष्ट रूप से और न ही इसके पाठ के किसी भी निहितार्थ के माध्यम से, नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन करता है। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकुर और जे. चेलमेश्वर भी हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पूर्वाग्रह पूर्ण व्याख्याता गलत व्याख्या का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हिला सकता है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद के सम्मान में नाम-निंदा से बचना ही समझदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सात सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा उच्च न्यायालयों के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों गोविंद माथुर, एस. मुरलीधर और संजीव बनर्जी ने भी बयान पर हस्ताक्षर किए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी. प्रवीण कुमार, ए. गोपाल रेड्डी, जी. रघुराम,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों, प्रत्याशियों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया

उन्होंने प्रदेश के विकास के कार्यों के लिये प्रतिबद्धता से काम करने का आव्हान किया

जयपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान2047 के संकल्प को तेजी से साकार करने के क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा, झालावाड़-बारां, टोंक-सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तोड़गढ़ , भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसदों एवं प्रत्याशियों तथा इन संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों, प्रत्याशियों तथा भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ गहन मंथन किया। इस दौरान शर्मा ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उनसे प्रदेश के विकास के कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आ ान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर जनसेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए है। संवाद के दौरान सांसद-विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में ऐतिहासिक निर्णयों से अभूतपूर्व बदलाव आए है। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सीपी जोशी भी उपस्थित थे।

- पहले दिन मुख्यमंत्री आवास पर हुए गहन मंथन में कोटा, झालावाड़-बारां, टोंक सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चितौड़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा के जनप्रतिनिधी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कोटा, झालावाड़-बारां, टोंक-सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ , भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, प्रत्याशियों तथा भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ गहन मंथन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज सरकार और संगठन बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। सांसद और विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी राज्य सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से गौरवान्वित हैं।

संवाद कार्यक्रम के पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नवाचार करते हुए जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद कार्यक्रम रखा। संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के 5 हजार गांवों को गरीबी मुक्त करने पर चर्चा की गई। इस हेतु प्रत्येक मापदंड के आधार पर कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि जनकल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में हम 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रहे है। साथ ही, 29 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सांसद खेल महोत्सव आयोजित करने की रूपरेखा भी बनाई है।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि कार्यक्रम में यह भी तय किया गया है कि सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों के मरम्मत और नवीन निर्माण कार्यों की सूची तैयार करके भेजेंगे। जिससे वहां शीघ्र कार्य शुरू हो सके।

संघ का तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम आज से

नई दिल्ली, 25 अगस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। संघ ने शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए दिल्ली में तीन दिवसीस संवाद कार्यक्रम करने का एलान किया गया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सोमवार को कार्यक्रम की जानकारी दी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि आरएसएस शताब्दी वर्ष दो अक्तूबर विजयादशमी से शुरू होगा। शताब्दी वर्ष पर संघ के विचारों को समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली में तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26, 27 और 28

- संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारी के सम्बंध में यह कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, जिसमें मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)